[श्री महेन्द्र सिंह माहरा]

भारत की सीमाओं पर तनाव पैदा कर रहा है। चीन पहले भी अरुणाचल पर अपने अधिकार की बात कह चुका है।

इस तरह की घटना कभी भी उत्तराखंड के सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में भी घट सकती है, तब हमारे पास अपनी सेनाओं को राज्य की चीनी सीमा पर भेजने के लिए सड़क नहीं होगी, क्योंकि टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग 1963 से 2013 तक 258 किलोमीटर की सड़क पूरी नहीं की जा सकी है। सीमा सड़क संगठन अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के बजाय सरकारी मशीनरी को दोष दे रहा है। बी.आर.ओ. का कहना है कि वन अधिनियम के कारण वन सम्बन्धी भूमि अधिग्रहण करने के लिए देर से स्वीकृति मिली। जबकि वन अधिनियम, 1980 में लागू हुआ था। निर्माण सामग्री मिलने में कठिनाई, बी.आर.ओ. द्वारा स्वयं पैदा की गई है, क्योंकि उस समय निर्माण सामग्री मिलने में कोई कठिनाई नहीं थी। आज की स्थिति यह है कि टनकपुर से पिथौरागढ़ मुख्यालय तक मोटर मार्ग का निर्माण भी पूरा नहीं हो पाया है और निर्माण कार्य में गुणवत्ता का अभाव है।

मैं सदन के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग के निर्माण में लापरवाही करना भविष्य में होने वाले खतरों से मुंह मोड़ना ही कहा जाएगा, क्योंकि बी.आर.ओ. का कहना है कि इस मार्ग का निर्माण 2019 में पूरा होगा, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। चीन ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा में ट्रेन पहुंचा दी, परन्तु हमारी सेना को अपने ही देश के अंतिम चेक पोस्ट लिपुलेक (ऊंचाई 19000 फीट) तक पहुंचने के लिए पैदल की अत्यधिक दुर्गम रास्तों को पार करने में 6 दिन लगते हैं, यह एक बड़ी विडम्बना है। हमारे पास सड़क निर्माण की सभी सुविधाएं होने के बावजूद भी इच्छा शक्ति का अभाव है। यह भी दुनिया का एक बड़ा आश्चर्य होगा - 50 वर्षों में 200 कि.मी. निर्मित मार्ग का सुधार न कर पाना तथा इससे आगे स्वीकृत स्थान लिपुलेक, जो चीन से लगी भारत की अन्तिम चौकी है, वहां तक सड़क न बन पाना।

अत: मेरा इस सदन के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि सीमा सड़क संगठन को सख्त आदेश दिया जाए कि वह टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग का अतिशीघ्र निर्माण करे, जो कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।

## Demand to take urgent measures to check the menace of human trafficking in the country

**श्रीमती माया सिंह** (मध्य प्रदेश) : महोदय, युनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एण्ड क्राइम्स (UNODC) की हाल ही में आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली मानव व्यापार का एक उभरता हुआ अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बनता जा रहा है, जो अत्यंत चिंताजनक बात है।

नेपाल, बांग्लादेश, पूर्वोत्तर राज्यों, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से बच्चों एवं युवतियों को अच्छी नौकरी का लालच देकर दिल्ली लाया जाता है, पर यहां आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें अगवा कर लिया गया है और फिर उनके शोषण का अंतहीन सिलसिला शुरू होता

है। इस तरह से घरेलू कामकाज के बहाने कम उम्र की बालिकाओं को देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में उनकी जबरन शादी करवा दी जाती है।

इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जो बच्चियां देह व्यापार के योग्य नहीं होतीं, उन्हें बेतिया, नट और कंजड़ जैसे समुदायों में युवा होने तक रखा जाता है और फिर युवा होने पर उन बालिकाओं को शारीरिक व्यापार के भयावह गलियारों में धकेल दिया जाता है, जहां उनके लिए हर दिन मरण समान है। महोदय, मैं शोषण की पराकाष्ठा का एक मामला सदन के समक्ष रख रही हूं। झारखंड की 14 वर्षीय दो लड़कियों को ऐसे ही माहौल से छुड़ा तो लिया गया, पर उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि दोनों ने झारखंड पहुंचने से पहले ही ट्रेन में दम तोड़ दिया।

महोदय, गायब होने वाले बच्चे अधिकतर गरीब परिवारों से होते हैं, उनके मां-बाप के पास इतना धन और समय नहीं होता है कि वे बार-बार थानों के चक्कर लगाएं। ऐसे लोगों के माता-पिता को कानूनी कार्यवाही हेतु तरह-तरह के कागजातों और सवाल-जबाव में उलझा कर उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है।

महोदय, मेरी यह मांग है कि ऐसे मामलों में प्रशासन तत्परता से कार्रवाई करे, तो संभवत: इस तरह की घटनाओं पर प्रारंभिक स्तर पर ही विराम लग सकेगा और प्रशासन की मुस्तैदी को देखते हुए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर विराम लगाया जा सकेगा।

## Demand to adopt three-language formula for secondary education under CBSE in the country

SHRI TARUN VIJAY (Uttarakhand): Sir, the National Policy on Education, 1986 enunciated as the Resolution of Parliament says that the State Government should adopt and vigorously implement the Three-Language Formula at the Secondary stage and two languages at Higher Secondary level.

The Curriculum Framework for School Education by NCERT also says that the study of all the three languages has to continue up to the end of the Secondary stage, and two languages at XI and XII.

All the State Boards of Secondary Education, except Tamil Nadu and some States, have three languages at the Secondary stage and two languages at Higher Secondary stage.

But the three National Boards, that is, CBSE, CISCE and NIOS do not implement the Three-Language Formula at the Secondary stage. They have two languages at the Secondary stage (IX, X) and one language at Higher Secondary stage (XI, XII). Three languages are taught in VI, VII and VIII only.